भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 238

मंगलवार, 02 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएम गतिशक्ति के तहत भू-स्थानिक डेटा

238. श्रीमती कमलजीत सहरावत:
श्रीमती कमलेश जांगड़े:
श्री दिनेशभाई मकवाना:
श्री विद्युत बरन महतो:
श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़:
श्री आलोक शर्मा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एकीकृत भू-स्थानिक इंटरफेस के माध्यम से शुरू किए गए प्रधानमंत्री गतिशक्ति पब्लिक प्लेटफॉर्म के उद्देश्य क्या हैं;

(ख) इस प्लेटफॉर्म पर वर्तमान में श्रेणीवार कौन-से डेटासेट और सेवाएँ उपलब्ध हैं और जनता के लिए डेटा सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित की जा रही है;

(ग) क्या इस पहल से अवसंरचनागत योजना और निवेश में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा मिलने की संभावना है;

(घ) यदि हाँ, तो ऐसी भागीदारी को सुगम बनाने के लिए प्रस्तावित तंत्र सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या राजसमंद सहित राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे के विकास में निवेश आकर्षित करने के लिए कोई विशेष पहल की गई है और यदि हाँ, इसलिए, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): अक्टूबर 2021 में शुरू की गई पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टरप्लान (पीएमजीएस एनएमपी) पहल, 58 से अधिक केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के डाटासेट को मिलाकर एक एकीकृत भू-स्थानिक मंच प्रदान करती है।

बजट 2025-26 की घोषणा के अनुरूप, दिनांक 13 अक्तूबर, 2025 को, एक

प्रश्न-आधारित तंत्र के माध्यम से, पीएम गतिशक्ति पब्लिक की शुरुआत की गई, यह पीएम गतिशक्ति पब्लिक पर मौजूद चुनिंदा डाटासेट के आधार पर निजी संस्थाओं के साथ डाटा विश्लेषण रिपोर्ट साझा करने का माध्यम है। इसकी मदद से सार्वजनिक/निजी क्षेत्र, परियोजना के प्रभाव क्षेत्र के दायरे में आने वाली सामाजिक-आर्थिक परिसंपत्तियों और अवसंरचना की परिकल्पना कर सकते हैं, विशिष्ट मानदंडों के आधार पर उपयुक्त स्थलों को चिन्हित कर सकते हैं, आवश्यक अनुमोदनों और एनओसी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सड़कों, पाइपलाइनों आदि जैसी रैखिक परियोजनाओं के लिए एलाइनमेंट की योजना बना सकते हैं। इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

i. नागरिकों, निजी संस्थाओं, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं आदि के लिए पीएम गतिशक्ति मंच तक आसान और उपयोगकर्ता के अनुकूल पहुंच प्रदान करना;
ii. निजी क्षेत्र द्वारा भू-स्थानिक डाटा के आधार पर निर्णय लेकर परियोजना की योजना को सक्षम करना।
iii. अवसंरचना और सामाजिक-आर्थिक परिसंपत्ति के लिए योजना बनाने में भू-स्थानिक डाटा के विश्लेषण के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देना;
iv. अवसंरचना की योजना और निवेश में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

सार्वजनिक/निजी व्यक्ति, राष्ट्रीय भू-स्थानिक डाटा रजिस्ट्री (एनजीडीआर) के माध्यम से यूआरएल: ugi.pmgatishakti.gov.in पर द्विस्तरीय प्रमाणीकरण पर आधारित स्व-पंजीकरण प्रक्रिया द्वारा पीएमजीएस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। वर्तमान में, इस पोर्टल पर केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लगभग 230 डाटा स्तरों पर आधारित डाटा विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार की जाती है।

(ङ): 'वर्ष 2022-23 में पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता स्कीम (एसएएससीआई)' के तहत पीएम गतिशक्ति से संबंधित व्यय हेतु, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (डीओई) ने, भाग- II के तहत दीर्घकालिक ऋण के रूप में सभी राज्यों के बीच संवितरण हेतु कुल 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, जिसमें राजस्थान राज्य की 07 परियोजनाएं भी शामिल हैं।

*****